



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 26 दिसम्बर, 2017

पौष 5, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2670/79-वि-1-17-1(क)-30-2017

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विनियोग (2017-2018 का अनुपूरक) विधेयक, 2017 पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2017 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश विनियोग (2017-2018 का अनुपूरक) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2017)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2017-2018 का अनुपूरक) अधिनियम, 2017 कहलायेगा।

2-ऐसे विविध परिष्य चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2018 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 11388,17,28,000 रुपये (रुपये ग्यारह हजार तीन सौ अट्ठासी करोड़ सत्रह लाख अट्ठाईस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2017-2018 के लिए

11388,17,28,000 रुपये का दिया जाना

विनियोग

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
02	आवास विभाग	राजस्व :	136.00 --	136.00
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	6721.35 --	6721.35
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	120.74 --	120.74
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	750.01 --	750.01
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	15000.00 --	15000.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	1183.40 --	1183.40
		पूंजी :	15835.60 --	15835.60
09	ऊर्जा विभाग	पूंजी :	75948.00 --	75948.00
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	4301.10 --	4301.10
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	3443.00 --	3443.00
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	2354.63 10.00	2364.63
		पूंजी :	41538.64 --	41538.64
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	121539.25 --	121539.25
		पूंजी :	1000.00 --	1000.00
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	1701.66 --	1701.66
		पूंजी :	42.85 --	42.85
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दूग्धशाला विकास)	राजस्व :	50.00 --	50.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	47.32 --	47.32

अनुसूची

--(क्रमशः)--

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपये में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
	(सहकारिता)			
		पूँजी :	--	409.03
				409.03
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	2129.80	--
				2129.80
22	खेल विभाग	राजस्व :	116.00	--
				116.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	पूँजी :	24992.00	--
				24992.00
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	700.00	--
				700.00
		पूँजी :	242.47	--
				242.47
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	15241.35	--
				15241.35
		पूँजी :	1245.52	--
				1245.52
30	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	30.00	--
				30.00
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	33835.35	--
				33835.35
		पूँजी :	8700.00	--
				8700.00
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	10193.74	--
				10193.74
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	29158.74	--
				29158.74
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	1185.00	--
				1185.00
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	5080.00	--
				5080.00
		पूँजी :	10000.00	--
				10000.00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	पूँजी :	20000.00	--
				20000.00
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	67.00	--
				67.00
		पूँजी :	3599.00	--
				3599.00
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	1000.00	--
				1000.00

अनुसूची

--(क्रमशः)--

1	2	3
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा राज्य की समेकित निधि पर स्वीकृत भारित योग
42	न्याय विभाग	राजस्व : 300.00 -- 300.00 पूंजी : 30000.00 -- 30000.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व : 148.00 -- 148.00 पूंजी : 182.54 -- 182.54
44	पर्यटन विभाग	राजस्व : 900.00 -- 900.00 पूंजी : 300.00 -- 300.00
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व : 10.00 -- 10.00
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व : 7400.00 -- 7400.00 पूंजी : 1000.00 -- 1000.00
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व : 24869.36 -- 24869.36
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 66.25 -- 66.25
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व : 170.00 -- 170.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	पूंजी : 51940.20 -- 51940.20
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व : 131.00 -- 131.00
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने)	राजस्व : 180000.00 -- 180000.00
68	विधान सभा सचिवालय	पूंजी : 890.39 -- 890.39
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व : 10320.22 -- 10320.22
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व : 40184.93 -- 40184.93 पूंजी : 5000.00 -- 5000.00
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व : 200.00 -- 200.00
74	गृह विभाग (होमगार्डस)	राजस्व : 10104.39 -- 10104.39
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक	राजस्व : 438.12 -- 438.12

अनुसूची

--(क्रमशः)--

1	2	3
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपये में)
क्रम संख्या	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित योग
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण) राजस्व :	3696.26 -- 3696.26
77	श्रम विभाग (सेवायोजन) राजस्व :	480.00 -- 480.00
78	सचिवालय प्रशासन विभाग राजस्व :	2565.00 -- 2565.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) राजस्व :	36250.50 -- 36250.50
80	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) राजस्व :	7477.50 -- 7477.50
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) राजस्व :	14611.33 -- 14611.33
	पूंजी :	9605.14 -- 9605.14
82	सतर्कता विभाग राजस्व :	152.30 22.50 174.80
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) राजस्व :	69783.14 -- 69783.14
	पूंजी :	139388.12 -- 139388.12
84	सामान्य प्रशासन विभाग राजस्व :	96.12 -- 96.12
	पूंजी :	5000.00 -- 5000.00
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) राजस्व :	304.00 -- 304.00
	पूंजी :	69.43 -- 69.43
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) राजस्व :	133.00 -- 133.00
92	संस्कृति विभाग राजस्व :	300.00 -- 300.00

अनुसूची

(समाप्त):

1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)			
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
		पूंजी :	512.30	--	512.30
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	10000.00	--	10000.00
		पूंजी :	14066.69	--	14066.69
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	100.00	--	100.00
	योग :	राजस्व :	677276.86	32.50	677309.36
		पूंजी :	461098.89	409.03	461507.92
	महायोग :		1138375.75	441.53	1138817.28

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद, राज्य विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से हो सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विनियोग (2017-2018 का अनुपूरक) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2670 (2)/LXXIX-V-1-17-1 (ka) 30-2017

Dated Lucknow, December 26, 2017

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Viniyog (2017-2018 ka Anupurak) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Shankhya 5 of 2017) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2017 :—

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION

(SUPPLEMENTARY 2017-2018)

ACT, 2017

(U. P. Act No. 5 of 2017)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2018.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation (Supplementary 2017-2018) Act, 2017. Short title

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 11388,17,28,000 (Rs. eleven thousand three hundred eighty eight crore seventeen lakh twenty eight thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2018 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the Schedule. Issue of
Rs.11388,17,28,000
out of the
Consolidated Fund
of the State of Uttar
Pradesh for the
Year 2017-2018

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2018. Appropriation

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

1	2	3
Grant/S	Services and	Sums not exceeding
		(In lakhs)
		Voted by the Legislative
		Charged on Consolidated
		Total
02	Housing Department	Revenue : 136.00 -- 136.00
03	Industries Department (Small Industry and Export Promotion)	Revenue : 6721.35 -- 6721.35
04	Industries Department (Mines and Minerals)	Revenue : 120.74 -- 120.74
05	Industries Department (Handloom and Village Industries)	Revenue : 750.01 -- 750.01
06	Industries Department (Handloom Industry)	Revenue : 15000.00 -- 15000.00
07	Industries Department (Heavy and Medium Industries)	Revenue : 1183.40 -- 1183.40
		Capital : 15835.60 -- 15835.60
09	Power Department	Capital : 75948.00 -- 75948.00
10	Agriculture and Other Allied Departments (Horticultural & Sericultur e Development)	Revenue : 4301.10 -- 4301.10
11	Agriculture and Other Allied Departments (Agriculture)	Revenue : 3443.00 -- 3443.00
13	Agriculture and Other Allied Departments	Revenue : 2354.63 10.00 2364.63

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3		
Grant/S	Services and	Sums not exceeding		
		(In lakhs)		
		Voted by the Legislative	Charged on Consolidated	Total
	(Rural Development)			
	Capital :	41538.64	--	41538.64
14	Agriculture and Other Allied Departments (Panchayati Raj)	Revenue : 121539.25	--	121539.25
	Capital :	1000.00	--	1000.00
15	Agriculture and Other Allied Departments (Animal Husbandry)	Revenue : 1701.66	--	1701.66
	Capital :	42.85	--	42.85
16	Agriculture and Other Allied Departments (Dairy Development)	Revenue : 50.00	--	50.00
18	Agriculture and Other Allied Departments (Co- oprative)	Revenue : 47.32	--	47.32
	Capital :	--	409.03	409.03
21	Food and Civil Supplies Department	Revenue : 2129.80	--	2129.80
22	Sports Department	Revenue : 116.00	--	116.00
24	Cane Development Department (Sugar Industry)	Capital : 24992.00	--	24992.00
25	Home Department (Jails)	Revenue : 700.00	--	700.00

SCHEDULE

--(Contd):

		(Contd.)			
1	2	3			
Grant/S	Services and	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the	Charged on	Total	
		Legislative	Consolidated		
		Capital :	242.47	--	242.47
26	Home Department (Police)	Revenue :	15241.35	--	15241.35
		Capital :	1245.52	--	1245.52
30	Confidential Department (Revenue Special Intelligence Directorate and Other	Revenue :	30.00	--	30.00
31	Medical Department (Medical Education and Training)	Revenue :	33835.35	--	33835.35
		Capital :	8700.00	--	8700.00
32	Medical Department (Allopathy)	Revenue :	10193.74	--	10193.74
35	Medical Department (Family Welfare)	Revenue :	29158.74	--	29158.74
36	Medical Department (Public Health)	Revenue :	1185.00	--	1185.00
37	Urban Development Department	Revenue :	5080.00	--	5080.00
		Capital :	10000.00	--	10000.00
38	Civil Aviation Department	Capital :	20000.00	--	20000.00
40	Planning Department	Revenue :	67.00	--	67.00
		Capital :	3599.00	--	3599.00

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/S	Services and	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the	Charged on	Total	
		Legislative	Consolidated		
41	Election Department	Revenue :	1000.00	—	1000.00
42	Judical Department	Revenue :	300.00	—	300.00
		Capital :	30000.00	—	30000.00
43	Transport Department	Revenue :	148.00	—	148.00
		Capital :	182.54	—	182.54
44	Tourism Department	Revenue :	900.00	—	900.00
		Capital :	300.00	—	300.00
46	Administrative Reforms	Revenue :	10.00	—	10.00
	Department				
48	Minorities Welfare	Revenue :	7400.00	—	7400.00
	Department	Capital :	1000.00	—	1000.00
49	Women & Child Welfare	Revenue :	24869.36	—	24869.36
	Department				
52	Revenue Department	Revenue :	66.25	—	66.25
	(Board of Revenue and other expenditure)				
54	Public Works	Revenue :	170.00	—	170.00
	Department				
	(Establishment)				
58	Public Works	Capital :	51940.20	—	51940.20
	Department				
	(Communications Roads)				
59	Public Works	Revenue :	131.00	—	131.00

SCHEDULE

(Contd):

1	2	3		
Grant/S	Services and	Sums not exceeding		
		(In lakhs)		
		Voted by the Legislative	Charged on Consolidated	Total
	Department (Estate Directorate)			
62	Finance Department (Superannuation Allowances and Pensions)	Revenue : 180000.00	--	180000.00
68	Legislative Assembly Secretariat	Capital : 890.39	--	890.39
70	Science and Technology Department	Revenue : 10320.22	--	10320.22
71	Education Department (Primary Education)	Revenue : 40184.93	--	40184.93
		Capital : 5000.00	--	5000.00
72	Education Department (Secondary Education)	Revenue : 200.00	--	200.00
74	Home Department (Home guards)	Revenue : 10104.39	--	10104.39
75	Education Department (State Council of Education Research & Training)	Revenue : 438.12	--	438.12
76	Labour Department (Labour Welfare)	Revenue : 3696.26	--	3696.26
77	Labour Department (Employment)	Revenue : 480.00	--	480.00

SCHEDULE

(Contd):

1	2	3
Grant/S	Services and	Sums not exceeding
		(In lakhs)
		Voted by the Legislative
		Charged on Consolidated
		Total
78	Secretariat Administration Department	Revenue : 2565.00 -- 2565.00
79	Social Welfare Department (Empowerment Of The Handicapped & Welfare Of Backward Classes)	Revenue : 36250.50 -- 36250.50
80	Social Welfare Department (Social Welfare & Welfare of Scheduled Castes)	Revenue : 7477.50 -- 7477.50
81	Social Welfare Department (Tribal Welfare)	Revenue : 14611.33 -- 14611.33
		Capital : 9605.14 -- 9605.14
82	Vigilance Department	Revenue : 152.30 22.50 174.80
83	Social Welfare Department (Special Com ponent Plan for Scheduled Castes)	Revenue : 69783.14 -- 69783.14
		Capital : 139388.12 -- 139388.12
84	General Administration Department	Revenue : 96.12 -- 96.12
		Capital : 5000.00 -- 5000.00

SCHEDULE

(Contd):

1	2	3			
Grant/S	Services and	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative	Charged on Consolidated	Total	
89	Institutional Finance Department (Commercial Tax)	Revenue :	304.00	--	304.00
		Capital :	69.43	--	69.43
90	Institutional Finance Department (Entertainment and betting Tax)	Revenue :	133.00	--	133.00
92	Culture Department	Revenue :	300.00	--	300.00
		Capital :	512.30	--	512.30
94	Irrigation Department (Works)	Revenue :	10000.00	--	10000.00
		Capital :	14066.69	--	14066.69
95	Irrigation Department (Establishment)	Revenue :	100.00	--	100.00
Total :		Revenue :	677276.86	32.50	677309.36
		Capital :	461098.89	409.03	461507.92
Grant Total :			1138375.75	441.53	1138817.28

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Article 205 read with Article 204 of the Constitution, an Appropriation Bill has to be introduced in the State Legislature after demands for Supplementary Grants have been voted by the Legislative Assembly.

This Bill provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the Supplementary Grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Supplementary Expenditure Charged on the Consolidated Fund of the State in respect of the financial year 2017-2018.

The Uttar Pradesh Appropriation (Supplementary 2017-2018) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.